अध्याय—तीन

औद्योगिक स्थिति

औद्योगिक उत्पादन के सूचक अंक में उतार-चढ़ाव

3.1 दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के शुरू से ही भारत की आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन में तेजी से वृद्धि करना रहा है। वर्ष, 1956 से 1964 तक इस उद्देश्य को पूरा करने में काफी प्रगति हुई और औद्योगिक उत्पादन में 8 प्रतिशत के वार्षिक औसत से वृद्धि हुई थी। लगता है कि उसके बाद औद्योगिक उत्पादन की वह रफ्तार नहीं रही। चौथी आयोजना में एक लक्ष्य औद्योगिक उत्पादन के औसत वार्षिक दर में 8 से 10 प्रतिशत की वृद्धि करना रखा गया था जो व्यवहार में केवल 3.9 प्रतिशत वार्षिक की ही हुई। आयोजना में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में अधिकांश उद्योगों का उत्पादन कम रहा और यह कमी विशेष रूप से उपभोक्ता वस्तुओं वाले उद्योगों के उत्पादन में हुई। इस प्रकार जहां वनास्पती जैसे उद्योगों में कमी के लक्षण दिखाई दिये वहां सूती कपड़ा, चीनी और साबुन जैसी अन्य महत्वपूर्ण उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में लगभग नगण्य वृद्धि हुई। पूंजीवाली वस्तुओं और कोयला, बिजली, उर्वरक, सीमेंट और एल्यूमिनियम जैसी अन्य महत्वपूर्ण अन्तर्वर्ती वस्तुओं में आम तौर पर वृद्धि के लक्षण दिखायी दिये। फिर भी कई एक उद्योगों में अपर्याप्त क्षमता का निर्माण होने तथा उत्पादन में काम आने वाली बिजली, कोयला और इस्पात जैसी वस्तुओं की कमी के कारण उत्पादन की प्रगति पर बुरा असर पड़ा। काफी अधिक पूंजी लगाने के बावजूद 1973–74 में तैयार इस्पात का उत्पादन वास्तव में 1968–69 में हुए उत्पादन से कम था और ऐसा लगता है कि इस कमी के कारण न केवल उत्पादन पर बुरा असर पड़ा बल्कि इसके कारण इंजीनियरी की वस्तुओं के निर्यात पर भी बुरा असर पड़ा।

3.2 औद्योगिक उत्पादन के नवीनतम आंकड़े जुलाई, 1974 महीने के हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि औद्योगिक उत्पादन में 1974 के पहले सात महीनों में 1973 की उसी अवधि की अपेक्षा केवल 2.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी 3.1)। बाद के महीनों के आंशिक आंकड़ों से पता चलता है कि कैलेण्डर वर्ष, 1974 में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि 2.5 प्रतिशत से अधिक नहीं हुई जबकि इसकी तुलना में 1973 में 0.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। मौजूदा संकेतों से लगता है कि 1974-75 के वित्त वर्ष में औद्योगिक उत्पादन में संभवतः लगभग 3.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी।

3.3 अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि वर्ष 1966 से औद्योगिक उत्पादन में जो अत्यन्त असंतोषजनक स्थिति चली आ रही है उसमें कोई अधिक सुधार होगा। चूंकि सरकार को उसके राजस्व का अधिकांश उद्योगों से मिलता है इसलिए औद्योगिक उत्पादन में लगातार मंदी रहने से सरकारी बचतों की वृद्धि पर बुरा असर पड़ा है और इसके कारण सरकारी क्षेत्र में लगायी जाने वाली पूंजी में वृद्धि करने की गुंजाइश भी कम हो गयी है। चूंकि भारत के निर्यात में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करना इस बात पर निर्भर है कि मुख्य रूप से मैन्यूफैक्चर किये जाने वाले सामान का तेज गति से उत्पादन किया जाय इसलिए औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि न होने से लगातार निर्यात की वृद्धि पर भी बुरा असर पड़ सकता है।

सारणी 3.1

औद्योगिक उत्पादन का सामान्य सूचक अंक

(अनन्तिम)

	(आधार 1960-100)		
मास	1972	1973	1974
जनवरी	199.6	207.4	206.0
फरवरी	196.7	191.8	196.2
मार्च	208.0	211.3	210.3
अप्रैल	190.4	188.6	191.3
मई	194.6	190.7	202.6
जून	196.8	192.2	202.4
जुलाई	196.8	199.1	203.5
अगस्त	198.6	204.9	
सितम्बर	198.6	199.3	
अक्टूबर	197.8	194.2	
नवम्बर	203.3	207.6	
दिसम्बर	211.7	222.0	
जनवरी-दिसम्बर	199.4	200.8 (+0.7)	
जनवरी-जुलाई	197.6	197.3 (—0.2)	201.8 (+2.3)

टिप्पणी :—कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष की घटती-बढ़ती को प्रतिशत में दिखाते हैं।

विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन

3.4 प्रमुख औद्योगिक वर्गों के अध्ययन से जिन्हें औद्योगिक उत्पादन के सरकारी सूचक अंक में शामिल किया गया है, पता चलता है कि जिन उद्योगों के उत्पादन में जनवरी से जुलाई, 1974 की अवधि में, 1973 की इसी अवधि की अपेक्षा वृद्धि हुई है उन उद्योगों का अंश सूचक अंक के कुल प्रतिशत में आधे से कुछ अधिक है। इन उद्योगों में बिजली, खनन और पत्थर निकालना, खाद्य वस्तुएं, पेय पदार्थ और तम्बाकू, कागज, रबड़ से बनी वस्तुएं, रासायनिक पदार्थ, पेट्रोलियम से बनने वाले पदार्थ, धातु रहित खनिज पदार्थ, धातु की वस्तुएं और बिजली की चीजें बनाने वाले उद्योग शामिल हैं। कपड़ा उद्योग में

औद्योगिक उत्पादन के सूचक अंक

(स्थूल अनुमान)

तिमाही औसत

1960=100

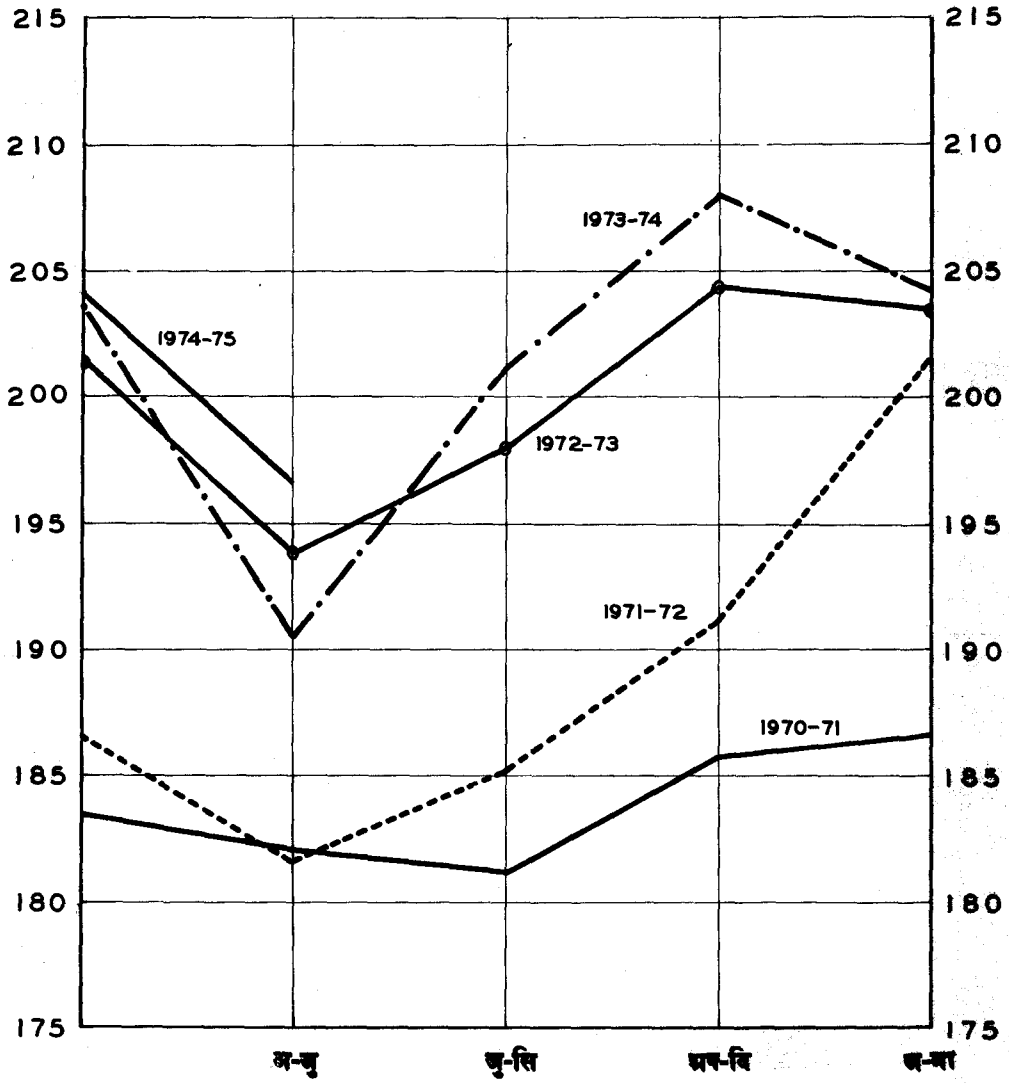

वित्त मंत्रालय, अर्थ प्रभाग

MCIPND-PLW-323/5/Fin/74-75-chart 4

(जिसका प्रतिशत एक चौथाई से अधिक है) कुछ भी वृद्धि नहीं हुई और अन्य उद्योगों के, जिनका कुल प्रतिशत में 20 प्रतिशत अंश होता है, उत्पादन में भी कमी हुई। इस वर्ग के उद्योगों में जूते, बेसिक मेटल, गैर बिजली की मशीनें, परिवहन उपकरण तथा लकड़ी और कार्क का सामान तैयार करने वाले उद्योग शामिल हैं (सारणी 3.2)। इसलिए जनवरी से जुलाई, 1974 तक की अवधि में औद्योगिक उत्पादन के समूचे सूचक अंक में केवल 2.3 प्रतिशत की वृद्धि होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

सारणी 3.2

मुख्य क्षेत्रों के अनुसार औद्योगिक उत्पादन के सूचक अंक

आधार : 1960=100

प्रतिशत अंश		1972	1973	1972 की तुलना में 1973 में घट-बढ़	1972	1973	1974	1972 की तुलना में 1973 में प्रतिशत घट-बढ़	1973 की तुलना में 1974 में प्रतिशत घट-बढ़
सामान्य सूचक अंक	100.00	199.4	200.8	+0.7	197.6	197.3	201.8	--0.2	+2.3
पैदा की गयी बिजली	5.37	390.7	383.8	—1.8	392.4	371.9	405.8	—5.2	+9.1
खानों और पत्थर खानों की खुदाई	9.72	164.2	163.6	—0.4	164.7	166.7	175.8	+1.2	+5.5
मैन्यूफैक्चर की गयी वस्तुएं	84.91	191.4	193.1	+0.9	189.0	189.4	191.8	+0.2	+1.3
खाद्य वस्तुएं	12.09	162.6	154.6	—4.9	153.5	151.1	152.8	—1.6	+1.1
पेय पदार्थ और तम्बाकू उद्योग	2.22	174.1	179.4	+3.0	172.3	172.1	189.1	—0.1	+9.9
वस्त्र	27.06	114.4	113.2	—1.0	112.9	108.9	108.9	—3.5	कुछ नहीं
फर्नीचर को छोड़कर लकड़ी और कार्क की वस्तुएं	0.80	217.8	158.4	--27.3	237.9	158.2	157.1	—33.5	—0.7
जूते आदि	0.21	150.8	151.3	+0.3	163.7	153.6	135.2	—6.2	—12.0
कागज और कागज से बनी वस्तुएं	1.61	226.1	236.4	+4.6	230.5	226.9	246.9	—1.6	+8.8
चमड़े और फर की वस्तुएं	0.43	59.9	76.4	+27.5	59.3	73.8	75.9	+24.5	+2.8
रबड़ की वस्तुएं	2.22	256.0	251.3	—1.8	257.2	235.9	269.3	—8.3	+14.2
रसायन और रासायनिक पदार्थ	7.26	293.7	301.9	+2.8	299.9	299.9	301.8	नहीं	+0.6
पेट्रोलियम रिफाइनरी में बनी वस्तुएं	1.34	317.2	332.8	+4.9	314.1	314.1	349.7	नहीं	+11.3
धातु भिन्न खनिज पदार्थ	3.85	225.2	227.1	+0.8	222.4	221.1	231.2	--0.6	+4.6
बेसिक मेटल उद्योग	7.38	225.3	215.8	—4.2	222.6	219.1	203.6	—1.6	—7.1
धातु से बनी वस्तुएं	2.51	242.7	243.1	+0.2	230.7	249.5	260.9	+8.1	+4.6
गैर-बिजली की मशीनें	3.38	402.7	454.9	+13.0	395.6	445.7	440.8	+12.7	—1.1
बिजली की मशीनें	3.05	435.0	436.2	+0.3	426.8	429.1	432.0	+0.5	+0.7
परिवहन उपकरण	7.77	133.5	148.1	+10.9	133.5	148.7	146.7	+11.4	—1.3
विविध उद्योग	1.23	86.5	74.5	—13.9	82.5	58.2	101.9	—29.5	+75.1

3.5 कुछ चुने हुए उद्योगों के आंकड़े जनवरी से सितम्बर, 1974 की अवधि के उपलब्ध हैं। इन आंकड़ों के विश्लेषण से औद्योगिक उत्पादन में कोई उल्लेखनीय सुधार होने का संकेत नहीं मिलता।

3.6 बुनियादी उद्योगों के वर्ग में वृद्धि केवल बिजली, कोयला और नाइट्रोजनी उर्वरकों के उत्पादन में हुई, बिजली के उत्पादन में 8.9 प्रतिशत, नाइट्रोजनी उर्वरक में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा कोयले का (लिग्नाइट सहित) उत्पादन 4.9 प्रतिशत बढ़ा। दूसरी ओर तैयार इस्पात और सीमेंट के उत्पादन में क्रमशः लगभग 3 प्रतिशत और 6 प्रतिशत की कमी हुई। इसी तरह एल्यूमीनियम और तांबे के उत्पादन में कमी हुई।

3.7 पूंजी वाली वस्तुओं के क्षेत्र में चीनी मिलों की मशीनों, चाय की पत्ती तैयार करने वाली मशीनों, रासायनिक पदार्थ और औषधियाँ तैयार करने की मशीनों, लुगदी और कागज बनाने वाली मशीनों, मोटर गाड़ियों के डीजल इंजनों, बायलरों, कनवेइंग और ड्रिलिंग के उपकरणों को तैयार करने वाले जैसे कई उद्योगों के उत्पादन मूल्य में जनवरी से सितम्बर 1974 की अवधि में 20 प्रतिशत से अधिक तक की वृद्धि हुई है। तथापि जहां तक उत्पादन के मूल्य में वृद्धि होने का संबंध कीमतों के बढ़ने से है इससे मूल में होने वाली घटती बढ़ती का कोई विश्वस्त संकेत नहीं मिलता। संभावना यही है कि कुछ एक उद्योगों को छोड़कर उत्पादन वास्तव में अधिक नहीं हुआ होगा। वस्तुतः इस तथ्य से कि कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों जैसे वाणिज्यिक मोटर गाड़ियों, इस्पात की ढली वस्तुओं, पावर के ट्रांसफार्मरों और खनन की मशीनों के उद्योग आदि के क्षेत्र में भी उत्पादन घटा है, यह संकेत मिलता है कि पूंजी वाली वस्तुओं के क्षेत्र में उद्योगों में वृद्धि की गति मन्द रही है।

3.8 साइकिल की ट्यूब और टायर, विस्कास स्टेपल फाइबर, वनास्पति से कमाई जाने वाली खालें और अखबारी कागज बनाने वाले कई एक उद्योगों के उत्पादन में जनवरी से सितम्बर, 1974 की अवधि के दौरान 15 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। लेकिन सूती धागे के उत्पादन में, जिसका सूती कपड़े के उत्पादन पर बहुत अधिक असर पड़ता है, केवल 2.7 प्रतिशत वृद्धि हुई। रंग रोगन, जूट की वस्तुएं, शीशे की चद्दरें और एल्यूमीनियम के कण्डक्टर बनाने वाले उद्योगों के उत्पादन में कमी हुई।

3.9 उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों में उत्पादन की घटती व बढ़ती का विश्लेषण करने से पता चलता है कि जनवरी से सितम्बर, 1974 के दौरान मिल के बने सूती कपड़े के उत्पादन में वर्ष 1973 की इस अवधि की तुलना में केवल 0.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि चीनी का उत्पादन 10.5 प्रतिशत बढ़ा लेकिन वनास्पती और जूतों का उत्पादन तेजी से घट गया। कमरे के एयरकंडीशनर, फ्लोरोसेंट ट्यूब, रेडियो, बिजली के पंखों, रेफरीजेटर और स्कूटर जैसी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। यात्री कारों के उत्पादनों में 2 प्रतिशत की कमी हुई।

औद्योगिक उत्पादन के गतिरोध के कारण

3.10 अवधि विशेष में होने वाला औद्योगिक उत्पादन दो बातों पर निर्भर करता है कि उत्पादक पूंजी कितनी मात्रा में उपलब्ध है और वर्तमान क्षमता का कितना उपयोग किया जाता है। निस्संदेह औद्योगिक वृद्धि पर उत्पादन-क्षमता में धीमी गति से विस्तार होने से बुरा असर पड़ता है। जैसा कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा हाल ही में किये गये एक अध्ययन में बताया गया है कि यदि उत्पादन क्षमता का उपयोग 80 प्रतिशत किया जाय तो औद्योगिक उत्पादन में 9 प्रतिशत की वार्षिक दर से तभी लगातार वृद्धि की जा सकती है जब कि उत्पादन क्षमता में प्रतिवर्ष लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाय क्योंकि उत्पादन शुरू होने से पहले लाजमी तौर पर कुछ समय लगता है। लेकिन, उसी अध्ययन के अनुसार चौथी आयोजना की अवधि में प्रमुख भारतीय उद्योगों में क्षमता 3.8 प्रतिशत वार्षिक की औसत दर से बढ़ी है।

3.11 पिछले छह वर्षों में उत्पादक-क्षमता में मामूली सी वृद्धि होने का कारण उद्योग और खनिज पदार्थों के उत्पादन में कम रफ्तार से पूंजी का लगाया जाना है। चौथी आयोजना में परिकल्पना की गयी थी कि उद्योग और खनिज पदार्थों पर सरकारी क्षेत्र में आयोजना परिव्यय के रूप में कुल 3,338 करोड़ रुपये की राशि लगायी जायगी। यह अनुमान 1968-69 की कीमतों के आधार पर लगाया गया था। उसके बाद से कीमतें बहुत अधिक बढ़ गयी हैं। फिर भी मौजूदा कीमतों के आधार पर वास्तविक परिव्यय 3,000 करोड़ रुपय से अधिक नहीं हुआ। जहां तक निजी और सरकारी क्षेत्रों का संबंध है, चौथी आयोजना में परिकल्पना की गयी थी कि इन क्षेत्रों में पांच वर्ष की अवधि में 2,250 करोड़ रुपया लगाया जायगा। हालांकि ब्यौरेवार सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है किन्तु ऐसा लगता है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में भी कम से कम वास्तविक रूप में, आयोजना में परिकल्पित लक्ष्यों की अपेक्षा कम पूंजी लगायी गयी। ऐसी असन्तोषजनक स्थिति होने का कारण वास्तविक बचतों में सामान्यतः कमी होना तो है ही पर इसके अलावा कई और कारण भी हैं जैसे परियोजनाएं शुरू करने और इन्हें पूरा करने में देरी होना आदि। लगता है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में, सीमेंट, टायर और ट्यूब, कागज और चीनी जैसे कई एक उद्योगों के क्षेत्र में पूंजी वाले नये उपकरणों की लागत में तेजी से वृद्धि हो जाने के कारण औद्योगिक क्षमता बढ़ाने पर बुरा असर पड़ा है।

3.12 वर्ष 1974-75 की वार्षिक आयोजना में सरकारी क्षेत्र में उद्योग और खनिज पदार्थों पर 1093 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था है जब कि इसकी तुलना में 1973-74 में 751 करोड़ रुपया खर्च होने की संभावना थी। इस राशि का दो-तिहाई से अधिक भाग इस्पात, अलौह धातुओं, उर्वरकों, कोयला, कच्चा लोहा, तेल की खोज और पैट्रोलियम जैसे बुनियादी उद्योगों पर खर्च किये जाने के लिए निर्धारित किया गया है। लेकिन पूंजी निवेश की धारणा में परिवर्तन होने एवं कीमतें बढ़ने के कारण अनुमान है कि 1974-75 में उद्योगों और खनिज पदार्थों पर लगायी गयी वास्तविक पूंजी की राशि 1973-74 से अधिक नहीं होगी।

क्षमता का उपयोग

3.13 पिछले छह वर्षों में धीमी गति से क्षमता का निर्माण होने और उपलब्ध क्षमता का अधिकतम उपयोग न कर सकने का औद्योगिक वृद्धि पर दुगुना बुरा असर पड़ा है। भारतीय औद्योगिक और विकास बैंक ने हाल ही में अनुमान लगाया है कि 40 मुख्य-मुख्य उद्योगों में क्षमता के उपयोग का अनुपात जो 1968-69 में 78 प्रतिशत था वह 1973-74 में घटकर 70 प्रतिशत रह गया है। पूंजी वाली वस्तुओं

औद्योगिक उत्पादन का स्वरूप

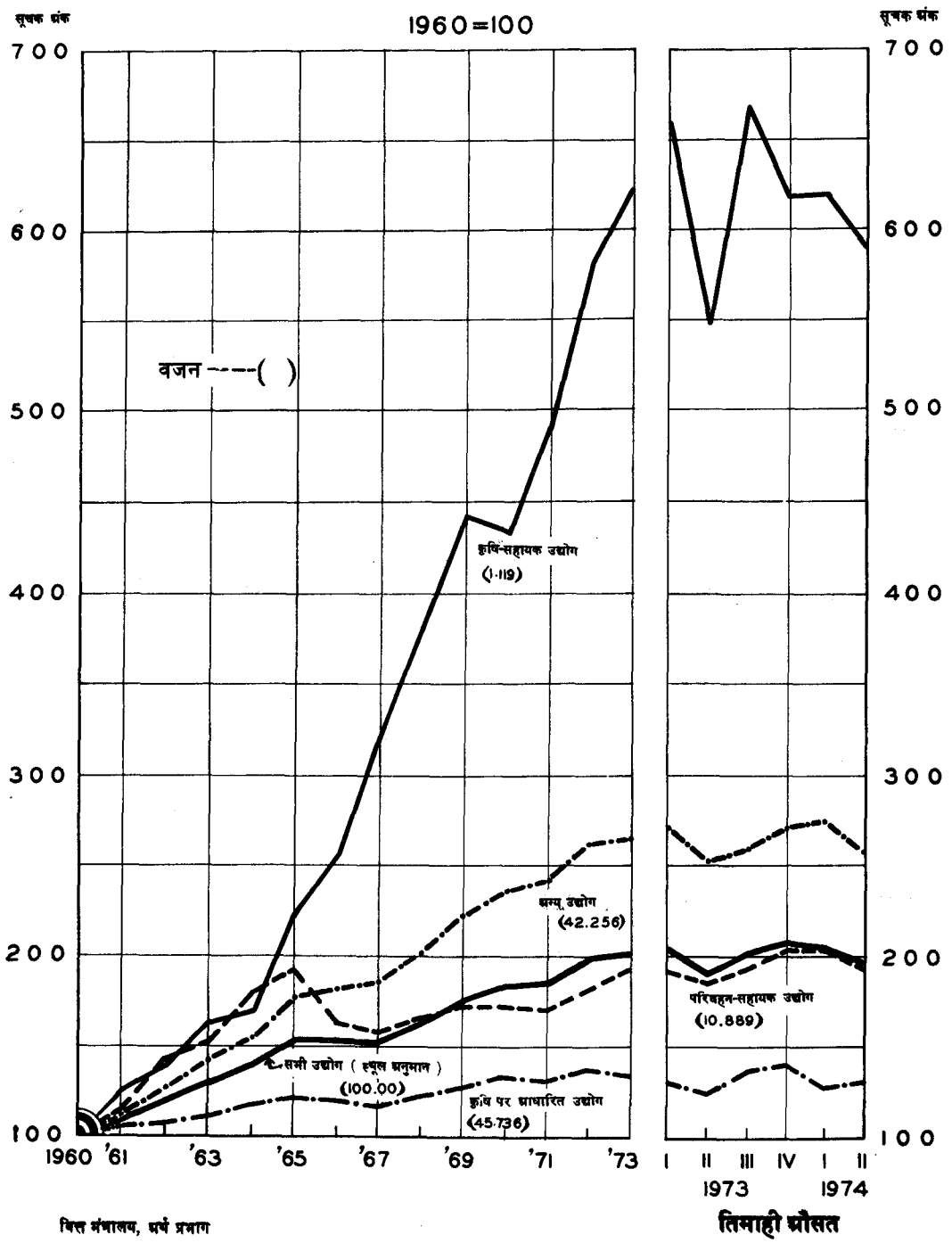

वित्त मंत्रालय, अर्थ प्रभाग

का क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां लगता है कि क्षमता के उपयोग में पिछले पांच वर्षों में सुधार हुआ है । हाल के आंकड़ों से लगता है कि सरकारी क्षेत्र में हैवी इंजीनियरी क्षेत्र के अनेक कारखानों के कार्य में सुधार होने के कारण पूंजीवाली वस्तुओं के संबंध में 1974-75 में क्षमता के उपयोग के अनुपात में और अधिक वृद्धि हो । लेकिन अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में क्षमता के उपयोग के अनुपात में काफी अधिक वृद्धि होने की संभावना नहीं है।

कृषि सम्बन्धी कच्चे माल की कमी

3.14 कई कारणों से भारतीय उद्योग में व्यापक रूप से ऐसी स्थिति बनी हुई है कि पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता । सबसे पहले हमें यह बात ध्यान में रखनी होगी कि कृषि पर आधारित उद्योगों का उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के सूचक अंक में 45 प्रतिशत से अधिक बैठता है और इन उद्योगों के उत्पादन में होने वाली घटबढ़ बाणिज्यिक फसलों की उपज के घटने व बढ़ने पर निर्भर करती है। जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है कि पिछले पांच या छः वर्षों में कपास, कच्चा जूट, गन्ना और वनास्पती बनाने वाले तेलहनों जैसी महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसलों की उपज में विशेष वृद्धि के कोई लक्षण नहीं दिखायी दिये हैं इसलिए सूती कपड़ा, वनास्पती, साबुन और चीनी जैसे उद्योगों के उत्पादन में जिसमें हालांकि प्रतिवर्ष घटती व बढ़ती होती रहती है, 1969-70 से कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई। इस प्रकार भारत की वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि न होने के परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की दर कम रही ।

बिजली का उत्पादन

3.15 हाल के वर्षों में उद्योगों के समूचे क्षेत्र को पर्याप्त मात्रा में पावर न मिल सकने के कारण क्षमता का पूरा पूरा उपयोग करने में बड़ी बाधा पहुंची है । केलेण्डर वर्ष 1973 में बिजली के उत्पादन में 1.8 प्रतिशत की कमी हुई जबकि वित्तीय वर्ष 1973-74 में इसमें 1972-73 की अपेक्षा 1.6 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई थी । मौसम की खराबी के कारण निस्सन्देह 1972-73 से बिजली के उत्पादन की गति धीमी रही । लेकिन यदि यह कहा जाय कि यह मौसम की खराबी जैसे छुट पुट कारणों से हुआ है तो इससे यह बात ठीक ठीक समझ में नहीं आती कि चौथी पंचवर्षीय आयोजना में 10.7 प्रतिशत की दर से बिजली का उत्पादन करने के लक्ष्य की तुलना में बिजली के उत्पादन में वृद्धि केवल 6.4 प्रतिशत की दर से ही क्यों हुई । जाहिर है कि हमारी अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र में किये गये कामों में कई एक कमियां रहीं ।

3.16 ध्यान देने की बात यह है कि बिजली के उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्यों में सबसे ज्यादा कमी चौथी आयोजना के दौरान ही हुई । आयोजना के दौरान पांच वर्षों में 93 लाख किलोवाट बिजली का वास्तविक उत्पादन करने का लक्ष्य था । निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले बिजली का वास्तविक उत्पादन केवल आधा हुआ । इस कमी के कई कारण थे जैसे लागत में क्रमानुसार वृद्धि हो जाना और बढ़ी हुई लागत को पूरा करने के लिए वित्तीय साधनों की कमी, इमारती सामान की तंगी की वजह से निर्माण कार्यों में देरी का होना, परियोजना का पूरी तरह से तैयार न होना, उपकरणों की सप्लाई में देरी होना आदि ।

3.17 पांचवीं आयोजना के दौरान बिजली की उत्पादन-क्षमता में 165 लाख किलोवाट की वृद्धि करने का विचार है । इसमें चौथी आयोजना से बचा हुआ काफी अधिक काम अर्थात् 108 लाख किलोवाट बिजली की वृद्धि करने का काम भी शामिल है । पांचवीं आयोजना में अतिरिक्त बिजली पैदा करने के लिए निर्धारित लक्ष्य सभी दृष्टिकोणों से काफी ऊंचा है । हालांकि उन सभी वर्तमान परियोजनाओं के पूरा हो जाने की आशा है जिनके अन्तर्गत 108 लाख किलोवाट की नयी क्षमता स्थापित की जानी है, फिर भी नयी परियोजनाओं से शेष 57 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन शुरू करने के लिए विशेष प्रयत्न करना होगा । इतना होने पर भी संभवतः पूर्वी क्षेत्र को छोड़ कर पांचवीं आयोजना की सारी अवधि में अन्य सभी क्षेत्रों में कम व अधिक मात्रा में पावर की तंगी बनी रहेगी । आशा है कि 1974-75 में बिजली की उत्पादन क्षमता में लगभग 15 लाख किलोवाट की वृद्धि हो जायगी ।

3.18 बिजली उत्पादन करने की उपलब्ध क्षमता का ठीक प्रकार से उपयोग न होने के कारण नयी क्षमता का निर्माण करने में बिजली की कमी से पड़ने वाला प्रभाव काफी बढ़ गया है । अनुमान लगाया गया है कि मशीनों की ठीक ढंग से देखभाल करने पर तापीय बिजली घरों से उत्पादित होने वाली बिजली के औसत उत्पादन में, हाल ही में संस्थापित 4100 के० डब्ल्यू० एच०/किलोवाट बिजली की क्षमता के मुकाबले, 20-25 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकेगी । कई तापीय बिजली घरों का काम ठीक से न चल पाने के कई ऐसे कारण थे जैसे कि कोयले की किस्म का घटिया होना, प्रायः समय पर स्पेयर पुर्जे न मिलने के कारण मशीनों की देखभाल के काम में चूक होना, प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी होना आदि । चालू वर्ष में सरकार ने इन बिजली घरों के काम में सुधार करने का भरसक प्रयत्न किया है । इस दिशा में किये गये प्रयत्नों में कुछ एक ऐसे काम शामिल हैं जैसे पूर्वी क्षेत्र में तापीय बिजली घरों—खास तौर से दामोदर घाटी निगम प्रणाली—के काम में सुधार लाने के लिये फौरी कार्यक्रम शुरू करना, विदेशी मशीनों के लिए आवश्यक स्पेयर पुर्जों का एक सामान्य पूल बनाने के लिये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा स्पेयर पुर्जे और सर्विसिंग प्रभाग की स्थापना करना, बिजली घरों को वास्तव में वही कोयला प्राप्त कराने की, जिसकी कि उन्हें आवश्यकता है, सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए कोयला खानों को बिजली घरों से जोड़ने की व्यापक व्यवस्था करना, केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण में कार्यचालन और अनुश्रवण निदेशालय की स्थापना करना, प्रशिक्षण सुविधाओं को और व्यवस्थित करना, राज्यों के सहयोग से प्रत्येक क्षेत्र में समेकित पावर प्रणाली का संचालन करना आदि । राज्य बिजली बोर्डों के प्रबन्ध को व्यावसायिक आधार पर और आधुनिक ढंग से चलाने का भी प्रस्ताव है ।

3.19 बिजली उत्पादन प्रणाली की कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए हाल में अपनाये गये उपायों के परिणाम सामने आ रहे हैं । इस प्रकार पूर्वी क्षेत्र के लिए अपनाये गये फौरी कार्यक्रम से दामोदर घाटी निगम प्रणाली में सबसे ज्यादा अर्थात् 800 मैगावाट बिजली का उत्पादन हुआ जो कि एक वर्ष पहले 350 मैगावाट था । मौजूदा लक्षणों के आधार पर 1974-75 में बिजली के उत्पादन में 1973-74 से लगभग 8-10 प्रतिशत वृद्धि होने की आशा है । फिर भी, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मोटे तौर पर अनुमान से संकेत मिलते हैं कि चार में से तीन प्रदेशों में बिजली की कमी जारी रहेगी ।

कोयले का मिल सकना

3.20 इस बात से कि पावर की सप्लाई में काफी सुधार होने पर भी औद्योगिक उत्पादन के कुल सूचकांक में 1974–75 में 3.5 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने की सम्भावना नहीं है इस बात का संकेत मिलता है कि काफी मात्रा में पावर की सप्लाई का होना जरूरी तो है लेकिन औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करने के लिए केवल यही काफी नहीं है । चालू वर्ष में विदेशों में पेट्रोलियम के पदार्थ मंगाने के खर्च में कटौती करने के लिए उद्योगों द्वारा भट्टी में इस्तेमाल किये जाने वाले तेल की खपत पर कुछ चुने हुए प्रतिबंध लगाने पड़े । अगर उद्योगों को कोयले की पर्याप्त सप्लाई के लिए कारगर व्यवस्था कर दी जाय तो इन प्रतिबन्धों से औद्योगिक उत्पादन पर कोई खास असर पड़ना जरूरी नहीं । फिर भी, यातायात की रुकावटों के कारण कई उद्योग अभी भी काफी मात्रा में कोयला न मिलने की शिकायत कर रहे हैं ।

3.21 यदि हम चाहते हैं कि जनवरी, 1974 से कच्चे तेल के मूल्य में तेजी से हुई वृद्धि का भारतीय अर्थव्यवस्था पर हानिकारक प्रभाव न पड़े तो खपत वाले क्षेत्रों तक कारगर ढंग से कोयला पहुंचाने की व्यवस्था करने के साथ साथ कोयले के उत्पादन में तेजी से वृद्धि करनी पड़ेगी । दुर्भाग्य से चौथी आयोजना में कोयले के उत्पादन में केवल 1.8 प्रतिशत वार्षिक की औसत से वृद्धि हुई जबकि आयोजना में 5.6 प्रतिशत के हिसाब से वृद्धि करने का लक्ष्य था । इसके अलावा, उद्योग में पूरी तरह से कोयले का इस्तेमाल करना शुरू करने से पहले यातायात व्यवस्था में काफी सुधार करना जरूरी होता है लेकिन अभी भी इस मामले में वास्तविक स्थिति और अभीष्ट स्थिति में पर्याप्त अंतर बना हुआ है । इन्हीं सब कारणों से, भारत के लिए बहुत कम आशा है कि वह भट्टी में काम आने वाले तेल की खपत को जल्दी ही घटा सकेगा ।

3.22 सौभाग्य से अब ऐसे संकेत मिले हैं कि कोयले के उत्पादन की वृद्धि की गति में तेजी आनी शुरू हो गयी है । बड़े पैमाने पर नयी परियोजनाओं पर पूंजी लगाने तथा बंद कोयला खानों को फिर से चालू करने का कार्यक्रम चल रहा है । अकेले वर्ष 1974–75 में ही कोयला उद्योग में लगभग 135 करोड़ रुपया लगाया जायगा । मजदूर-मालिक संबंधों और श्रमिक कुशलता में सुधार लाने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से बहुत से दिहाड़ी पर काम करने वाले और ठेके के मजदूरों को नियमित कर्मचारी बना दिया गया है और उनकी मजदूरी में काफी अधिक वृद्धि कर दी गयी है । इस समय कोयला सप्लाई करने की एक अधिक युक्तिसंगत योजना पर विचार किया जा रहा है जिसमें बड़े बड़े औद्योगिक केन्द्रों में विशाल भण्डार बनाना भी शामिल है ।

3.23 अप्रैल से दिसम्बर, 1974 के दौरान कोयले का उत्पादन 624 लाख मेट्रिक टन हुआ जबकि 1973 की इसी अवधि में 570 लाख मेट्रिक टन कोयले का उत्पादन हुआ था । आशा है कि 1974-75 में 870 लाख मेट्रिक टन कोयले का उत्पादन होगा जो 1973-74 की तुलना में लगभग 11.5 प्रतिशत अधिक होगा । किन्तु, चूंकि कोयले के उत्पादन के 900 लाख मेट्रिक टन के निर्धारित लक्ष्य से कम रहने की सम्भावना है इसलिए कुछ और समय के लिए कोयले की कमी महसूस की जाती रहेगी ।

इस्पात का मिल सकना

3.24 काफी मात्रा में पूंजी लगाने के बावजूद चौथी आयोजना के अन्तिम वर्ष में कोयले का उत्पादन आयोजना के पहले वर्ष के उत्पादन की अपेक्षा कम रहा । वास्तव में चौथी आयोजना के दौरान तैयार इस्पात का उत्पादन लगभग 1 प्रतिशत वार्षिक की औसत से घट गया । क्षमता के उपयोग का अनुपात जो 1968-69 में 71 प्रतिशत था 1973-74 में घटकर 57 प्रतिशत रह गया । यह स्थिति बिजली की कमी, कोयले की अपर्याप्त सप्लाई और दुर्गापुर तथा राउरकेला के कारखानों में मजदूर मालिक सम्बन्धों के बिगड़ जाने के कारण पैदा हुई । वर्ष 1973-74 में तैयार इस्पात का उत्पादन 1972-73 के उत्पादन की अपेक्षा 5 लाख मेट्रिक टन कम रहा । देश में उत्पादन के कम होने के कारण काफी अधिक मात्रा में विदेशों से इस्पात मंगाना पड़ा था, फिर भी कमी बनी रही । इस प्रकार इस्पात के उत्पादन की कमी हाल के वर्षों में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के मार्ग में एक और बाधा बन गयी है ।

3.25 पिछले कुछ महीनों में इस्पात कारखानों की कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाये गये हैं । दामोदर घाटी निगम द्वारा पैदा की जा रही बिजली में और सुधार किय जाने से निःसन्देह क्षमता का अधिक उपयोग किये जाने में आसानी रहेगी । दीर्घावधिक उपाय के रूप में भिलाई इस्पात कारखाने के लिए अतिरिक्त बिजली उत्पादन करने की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है । इसी प्रकार राउरकेला में और दुर्गापुर में बिजली उत्पादन में वृद्धि करने के सम्बन्ध में भी तत्परता से विचार किया जा रहा है । भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने भी एक ऐसी योजना बनायी है जिसके अन्तर्गत इस्पात कारखानों के पास कोयले और कोक के प्रारक्षित भण्डार रखे जाने हैं जिससे संकट की किसी भी स्थिति का सामना किया जा सके ।

3.26 उपलब्ध आंकड़ों से लगता है कि मुख्य उत्पादकों द्वारा 1974-75 में लगभग 50 लाख मेट्रिक टन बिक्री योग्य इस्पात तैयार किया जायगा जबकि इसके मुकाबले में 1973-74 में 41 लाख मेट्रिक टन इस्पात का उत्पादन किया गया था । इस्पात के उत्पादन में वृद्धि होने और चालू ऋण नीति के परिणामस्वरूप अत्यधिक मात्रा में इन्वेंटरी का सामान जमा करने के लिए प्रोत्साहन न मिलने से मांग और पूर्ति के बीच के अन्तर के कुछ कम होने की सम्भावना है । वर्ष 1975-76 में बोकारो स्थित कारखाने के चालू हो जाने की आशा है जिससे बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन बढ़कर लगभग 60 लाख मेट्रिक टन हो जायगा । इससे इस्पात की बढ़ी हुई मांग काफी हद तक पूरी हो सकेगी और विदेश से मंगाये जाने वाले इस्पात की मात्रा में भी कुछ कमी करना आसान होगा ।

सीमेंट

3.27 उद्योग में काम आने वाली एक और बुनियादी वस्तु सीमेन्ट है जिसके अभाव से निर्माण कार्यों में पूंजी लगाने में लगता है कि बाधा आने लगी है । वर्ष 1973-74 में इसका उत्पादन वर्ष 1972-73 के 155 लाख मेट्रिक टन से कम होकर 147 लाख मेट्रिक टन रह गया । चौथी आयोजना की अवधि में इसके उत्पादन में प्रति वर्ष 3.8 प्रतिशत के हिसाब से वृद्धि हुई जबकि इसके उत्पादन का लक्ष्य 8.1 प्रतिशत का था । इसकी उत्पादन क्षमता के उपयोग का अनुपात 1968-69 के 79 प्रतिशत से कम होकर 1973-74 में 76 प्रतिशत रह गया ।

3.28 प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि 1974-75 में इसके उत्पादन और इसकी उत्पादन क्षमता के उपयोग में और अधिक कमी हुई । वर्ष 1974-75 के पहले नौ महीनों में सीमेन्ट का उत्पादन वर्ष 1973-74 की इसी अवधि की अपेक्षा 3.5 प्रतिशत कम हुआ । चालू वर्ष में उत्पादन में कमी होने के मुख्य कारण पावर में भारी कटौती और कोयले की सप्लाई में कमी तथा खपत केन्द्रों तक सीमेन्ट ले जाने के लिए रेल के बन्द डिब्बों का पर्याप्त संख्या में प्राप्त न होना था । सीमेन्ट की बहुत ज्यादा मांग को देखते हुए सरकार ने कम प्राथमिकता वाले कामों में सीमेन्ट के इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध लगा दिया और सीमेन्ट (संरक्षण तथा इस्तेमाल की विनियमन) आदेश, 1974 के अन्तर्गत कुछ श्रेणियों की इमारतों के निर्माण में जिनका निर्माण कुर्सी के स्तर तक नहीं पहुंचा था, सीमेन्ट के इस्तेमाल पर एक वर्ष के लिए रोक लगा दी गयी है । फिर भी, मांग और सप्लाई के बीच उचित सन्तुलन रखने की सुनिश्चित व्यवस्था तभी हो सकती है जब उत्पादन क्षमता में तेजी से विस्तार किया जाय । इस समय 189 लाख मेट्रिक टन की अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने के लिए दिये गये लाइसेंसों और आशय-पत्रों को क्रियान्वित किया जाना बाकी है । चूंकि पूंजी लागत बढ़ती जा रही है और उत्पादक समझते हैं कि कानूनी तरीके से निर्धारित की गयी कीमतें अधिक लाभदायक नहीं हैं इसलिए उक्त काम में ढील आ गयी है ।

देशीय क्रय-बिक्रय को आवश्यकता से अधिक सुरक्षा प्रदान करने का वातावरण

3.29 ऊपर जिन बाधाओं का उल्लेख किया गया है उनके अलावा इस तथ्य को नहीं भुलाया जाना चाहिए कि विदेशों से मंगाये जाने वाले माल की मात्रा पर कड़ा नियंत्रण रखने की हमारी प्रणाली से देश में औद्योगिक वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजार अत्यधिक सुरक्षित सा बन गया है जिसकी वजह से लागत और कीमत कम करके उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा का अधिकतर अभाव हो गया है । इस प्रकार के वातावरण में वास्तविक स्थिति उत्पादन में वृद्धि के अनुकूल होने पर भी उद्योगों की प्रायः यह प्रवृत्ति रहती है कि कम उत्पादन करके कीमतें बढ़ायी जांय और अधिक लाभ कमाया जाय । वर्ष, 1974 के आखिरी महीनों में सूती वस्त्र उद्योग का रवैया स्पष्टतया इसी ढंग का था । दुर्भाग्य से हमारी विदेशी मुद्रा की देनदारी की मौजूदा स्थिति में आयात के विषय में ऐसी उदारता बरतना व्यावहारिक नहीं है जिससे कि भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता शुरू की जा सके इसलिए प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रणालियों को बढ़ने से रोकने के लिए अन्य उपाय खोजने होंगे ।

मंदी और पूंजी लगाने के लिए वातावरण

3.30 उद्योगों की हाल की स्थिति के बारे में पहले जो समीक्षा की गयी है उसमें एक मुख्य विषय यह है कि भारत की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था की गति धीमी रहने का कारण मूलतः यह है कि उद्योग और खनिज में वास्तव में सन्तोषजनक रूप में पूंजी नहीं लगती और ऐसी अड़चनें सामने आती हैं जिनसे उद्योगों द्वारा उपयोग में लायी जाने वाली आवश्यक मदों जैसे बिजली, कोयला, इस्पात, सीमेन्ट और कृषि जन्य कच्चे माल आदि के उत्पादन में वृद्धि करने में रुकावटें आती हैं । विचार करने की बात है कि 1974 के आखिरी महीनों से कुछ क्षेत्रों में जो शोर है कि आर्थिक शिथिलता का खतरा आ रहा है उसका इस स्थिति में क्या अर्थ हो सकता है ?

3.31 यदि इसका उद्देश्य भारतीय उद्योग द्वारा हाल के वर्षों में किये गये निराशाजनक कार्य की ओर ध्यान आकर्षित करना है तो इस बारे में मतभेद नहीं हो सकता । लेकिन यदि आर्थिक शिथिलता का अनुमान इस मान्यता पर आधारित है कि सरकार द्वारा 1974 की दूसरी छमाही में मूल्य-वृद्धि को रोकने के लिए जो उपाय अपनाये गये हैं उनसे औद्योगिक क्रियाकलाप की गति में और अधिक कमी होगी तो इस प्रकार के तर्क में स्पष्टतः कोई जान नहीं है । इसके अलावा यह समझना भी जरूरी है कि उत्पादन के काम में आने वाली कुछ अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई में रुकावट आ जाने के कारण जो औद्योगिक गतिरोध आ गया है उसे विस्तारकारी वित्तीय व मुद्रा नीति के मिश्रण द्वारा मांग में सामान्य सुधार लाकर कारगर ढंग से ठीक नहीं किया जा सकता । यदि औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए इतना ही करना काफी होता तो वाणिज्यिक क्षेत्रों को दिये जाने वाले ऋणों में 1973-74 में की गयी वृद्धि से औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि की गति में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती ।

3.32 इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सरकारी क्षेत्र में पूंजी लगाये जाने की रफ्तार कम होने का पूंजी वाली वस्तु के कुछ उद्योगों के उत्पादन की मांग पर प्रभाव पड़ सकता है । लेकिन उद्योग में पूंजी लगाने में गतिरोध का मूल कारण कीन्स की शब्दावली में वास्तविक बचतों में कमी आ जाना है, न कि मांग का साधारण रूप से गिर जाना।

3.33 जैसा कि अनुभव रहा है इस बात का कोई विश्वस्त प्रमाण नहीं है कि 1974–75 की दूसरी छमाही में औद्योगिक वृद्धि की रफ्तार कुल मिलाकर पहली छमाही से कम रहेगी । वस्तुतः प्राप्त प्रमाणों से बिल्कुल विपरीत लक्षणों का संकेत मिलता है । लेकिन इसका अर्थ इस तथ्य को अस्वीकार करना नहीं है कि कुछ उद्योगों का उत्पादन नहीं घट सकता या ऋण प्रतिबन्धों के कारण कुछ उद्योगों को स्थिति में तालमेल बैठाने में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऐसी घटनाएं तेजी से विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था में भी आम तौर से होती ही रहती हैं। इस प्रकार के क्षेत्रीय असन्तुलनों से यह भ्रान्ति नहीं होनी चाहिए कि अर्थ-व्यवस्था में मांग में सामान्य कमी हो गयी है। अब स्थिति यह है कि ऋण–प्रतिबन्धों के लगने से इन्वेंटरी वाले कुछ अत्यावश्यक कच्चे माल के स्टाक में कुछ कमी हुई है लेकिन इन प्रतिबन्धों के कारण संपूर्ण औद्योगिक उत्पादन के स्तर पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए । कपड़ा उद्योग की एक समय यह शिकायत थी कि उसके पास बहुत अधिक तैयार माल एकत्रित हो गया है लेकिन लगता है कि यह उद्योग उन अस्थायी कठिनाइयों पर काबू पाने में सफल हो गया है । वास्तव में ऐसा लगता है कि अब इस उद्योग का अपनी मांग की संभावना के बारे में इतना आशावादी दृष्टिकोण है कि यह अपने उत्पादन की कीमतें बढ़ाने के प्रलोभन से दूर नहीं रह सका । मोटर गाड़ियों के क्षेत्र में उत्पादन बहुत अच्छा नहीं है । लेकिन लगता है कि इस क्षेत्र में भी दिसम्बर, 1974 में बिक्री के काम में फिर से जान आ गयी है । इसके अलावा 1974-75 की औद्योगिक दर का विश्लेषण करने में इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, हिन्दुस्तान केबल्स, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स तथा माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन जैसे सरकारी क्षेत्र के अनेक उद्यमों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है ।

3.34 जहां तक पूंजी लगाने की इच्छा का संबंध है, उसके बारे में जो भी थोड़े प्रमाण प्राप्त हुए हैं उनसे पता चलता है कि इसमें विशेष वृद्धि नहीं हुई है किन्तु इसमें भारी कमी होने की आशंका के

लक्षण भी नहीं दिखाई देते। वर्ष 1974 में जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या 1099 और आशय पत्रों की संख्या 1180 थी जो 1973 के दौरान जारी किये गये 596 लाइसेंसों और 899 आशयपत्रों की संख्या से काफी अधिक है। अप्रैल-दिसम्बर 1974 की अवधि के दौरान पूंजीवाली वस्तुओं के लिए 146.66 करोड़ रुपये के लाइसेंस जारी किये गये जबकि 1973 की इसी अवधि के दौरान 107.93 करोड़ रुपये के लाइसेंस जारी किये गये थे। रासायनिक पदार्थों और इंजीनियरी के सामान के लिए दिये गये लाइसेंसों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। जहां तक गैर सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा पूंजी जुटाने का सम्बंध है वर्ष 1974 में इन कंपनियों द्वारा 59.11 करोड़ रुपये (बोनस निर्गमों को छोड़कर) की पूंजी जुटायी गयी जबकि 1973 में 74.35 करोड़ रुपये की पूंजी जुटायी गयी थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि जुलाई-दिसम्बर 1974 की अवधि में जो पूंजी (अनुमानतः 19.10 करोड़ रुपये) जुटायी गयी थी वह वर्ष की पहली छमाही में जुटायी गयी 40.01 करोड़ रुपये की पूंजी से काफी कम थी। लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिए कि अधिकांश कमी का कारण ऋण-पत्र हैं। यदि सामान्य शेयरों और तरजीही शेयरों को ही हिसाब में लिया जाय तो पता चलेगा कि इनके माध्यम से जुलाई-दिसम्बर 1974 के दौरान 18.10 करोड़ रुपये की रकम जुटायी गयी थी जबकि जनवरी-जून 1974 में इनके द्वारा 21.51 करोड़ रुपये की रकम जुटायी गयी थी। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जुलाई 1974 से, जब लाभांशों की घोषणा करने पर प्रतिबन्ध लगाये गये थे, शेयरों की कीमतों में मंदी बनी रही और यह प्रतीत होता है कि इससे निवेशकों और हामीदारों के मन में हिचकचाहट पैदा हो गयी है। फिर भी लाभांशों पर लगायी गयी पाबन्दी से निगमित कंपनियों के आन्तरिक साधनों में जितनी वृद्धि होगी उतनी ही सीमा तक उनकी विस्तार क्षमता बढ़ जायगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जारी किये गये नये शेयरों से कम पूंजी एकत्रित हुई है तो इससे नये शेयरों की बिक्री की मात्रा से पूंजी लगाये जाने के विषय में कोई पक्के निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। सावधि ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा वित्त-पोषित परियोजनाओं में लगायी गयी पूंजी की घटा-बढ़ी को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि 1974-75 में 1973-74 की अपेक्षा गैर-सरकारी औद्योगिक क्षेत्र में वास्तविक रूप में कम पूंजी नहीं लगायी गयी होगी। इसके अलावा, इन संस्थाओं से सहायता प्राप्त करने के लिए बढ़ती हुई मांग से पता चलता है कि सरकार द्वारा पिछले कुछ महीनों में अपनाये गये विभिन्न मूल्य वृद्धि विरोधी उपायों का पूंजी लगाने की इच्छा पर बुरा असर नहीं पड़ा है।

3.35 निस्संदेह, इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि औद्योगिक देशों में भारी आर्थिक शिथिलता होने का हमारे निर्यात की वृद्धि पर कुछ बुरा असर पड़ सकता है और इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन पर भी बुरा असर पड़ सकता है। आर्थिक सहायता और विकास संघ ने हाल ही में यह कहा है कि लगातार दूसरे साल भी 1975 में बड़े औद्योगिक देशों में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं होगी। फिर भी, अभी से, अधिकांश औद्योगिक देश अपनी आर्थिक नीतियों को नियंत्रित विस्तार करने की दिशा की ओर मोड़ रहे हैं। इससे 1975 की दूसरी छमाही में इन देशों में आर्थिक क्रियाकलाप में फिर से तेजी आने की संभावना है। यदि ऐसा न भी हो तो भी यह देखते हुए कि संसार में मैन्यूफैक्चर की जाने वाली वस्तुओं के व्यापार में भारत का थोड़ा ही हिस्सा है, यदि निर्यात को तेजी से बढ़ा देने की नीति अपनायी गयी तो औद्योगिक देशों की आर्थिक शिथिलता से हमारे देश के निर्यात के स्तर पर संभावित रूप से पड़ने वाला बुरा प्रभाव दूर हो जायगा।

औद्योगिक लाइसेन्स देने की नीति

3.36 औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने तथा इनके संबंध में अन्य स्वीकृतियां देने में होने वाली प्रशासनिक देरी को कम करने के लिए नवम्बर, 1973 में परियोजना अनुमोदन बोर्ड और एकीकृत औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय की स्थापना की गयी थी। इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि इन संस्थागत सुधारों से प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाने में सहायता मिली है। इस सचिवालय की स्थापना के समय 3800 आवेदन पत्रों पर विचार किया जाना था। अगस्त, 1974 के अन्त तक इनमें से 3000 से भी अधिक आवेदन-पत्रों का फैसला किया जा चुका था। इसके कार्यचालन के प्रथम वर्ष (नवम्बर 1973 से अक्टूबर 1974) में 5572 आवेदन-पत्रों का अंतिम रूप से निपटारा किया गया। इससे पहले किसी भी एक वर्ष में इतनी बड़ी संख्या में आवेदन-पत्र नहीं निपटाये गये थे। लाइसेंसों के आवेदन-पत्रों में से 79 प्रतिशत आवेदनपत्रों का निपटारा 120 दिन में, संयुक्त आवेदन-पत्रों में से 83 प्रतिशत आवदन-पत्रों का निपटारा 120 दिन में तथा एकाधिकार और प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रणाली के अधीन प्राप्त आवेदनपत्रों में से 73 प्रतिशत आवेदनपत्रों का निपटारा 150 दिन में किया गया। पूंजी वाली वस्तुओं के आयात के लिये स्वीकृतियों देने में लगने वाले समय में भी काफी कमी हुई है। औद्योगिक अनुमोदनों का कार्यान्वियन करने की प्रगति की सूचना देने में सुधार करने का भी प्रस्ताव है ताकि व्यर्थ जाने वाले लाइसेंस देने से बचा जा सके और इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था की जा सके कि उद्यमकर्ता लाइसेंसों की स्वीकृति की अवधि के दौरान परियोजनाओं पर अमल करने के लिए पर्याप्त कदम उठायें। इस उद्देश्य से कि उपलब्ध क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग करने में आसानी रहे, बिजली उपकरणों, मशीनी औजारों और मशीनों के निर्माताओं को यह छूट दे दी गयी है कि वे अपने उत्पादन के स्वरूप में मांग के बदलने के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं।

औद्योगिक सम्बन्ध

3.37 वर्ष, 1974 का आरम्भ बम्बई की सूती कपड़ा मिलों में हड़ताल होने के कारण कुछ निराशा के वातावरण में हुआ। यह हड़ताल 9 फरवरी तक जारी रही। तमिलनाडु में भी सूती कपड़ा मिलें फरवरी के सारे महीने बंद रहीं। औद्योगिक अशांति रहने के कारण जूट उद्योग में भी मध्य जनवरी से मध्य फरवरी तक उत्पादन में कमी हुई। काम के घण्टों की औसत संख्या जो जनवरी-फरवरी, 1973 में 384 थी, जनवरी-फरवरी, 1974 में घटकर 168 रह गयी। काम का कुल समय बर्बाद जाने के बारे में इन दो बड़े उद्योगों म 1974 की पहली छमाही में 260 लाख श्रम दिवस बर्बाद होने की सूचना मिली है। हालांकि बाद की छमाही के आंकड़े प्राप्त नहीं हैं, परन्तु यह ध्यान देने की बात है कि साल की पहली छमाही में जो श्रम-दिवस बर्बाद हुए उनकी संख्या पहले किसी भी वर्ष में बर्बाद हुए कुल श्रम-दिवसों से काफी अधिक थी। रेलवे जैसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा में मई, 1974 में हुई हड़ताल से आर्थिक क्रियाकलाप की सामान्य गति में बाधा पहुंची हालांकि यह हड़ताल केवल आंशिक रूप से सफल हुई थी।

संगठित क्षेत्र में रोजगार

3.38 संगठित क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादन की गति धीमी होने के बावजूद 1973-74 में रोजगार में 2.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मैन्यूफैक्चरिंग के क्षेत्र में रोजगार में 2.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बिजली

उत्पादन और व्यापार तथा वाणिज्य में रोजगार में क्रमशः 5.5 प्रतिशत और 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। व्यापार तथा वाणिज्य के क्षेत्र में वृद्धि का कारण सरकारी क्षेत्र के क्रियाकलाप में वृद्धि होना है।

3.39 क्षेत्रों के अनुसार, संगठित क्षेत्र में 1973-74 के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर, रोजगार में सबसे ज्यादा वृद्धि (4.0 प्रतिशत) उत्तरी क्षेत्र में हुई। लगभग इतनी ही वृद्धि (3.7 प्रतिशत) पूर्वी क्षेत्र में हुई। उत्तरी क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि जम्मू और कश्मीर (11.8 प्रतिशत), हरियाणा (6.1 प्रतिशत) और पंजाब (5.8 प्रतिशत) में हुई और पूर्वी क्षेत्र में बिहार में सबसे अधिक अर्थात् 7.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अलग अलग राज्यों में कर्नाटक राज्य में सब राज्यों से अधिक अर्थात् 17.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

3.40 जून, 1974 के अन्त में, रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में बेरोजगार व्यक्तियों की कुल संख्या 83.54 लाख थी जो पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 10 प्रतिशत अधिक थी। फिर भी, इस अवधि के दौरान जुलाई, 1972 से जून, 1973 तक की अवधि की अपेक्षा काफी कम वृद्धि हुई है। जुलाई, 1972 से जून, 1973 की अवधि में काफी अधिक वृद्धि अर्थात् 33 प्रतिशत हुई। बेरोजगार शिक्षितों की संख्या जून 1974 को समाप्त हुए वर्ष में 5 लाख से बढ़कर 40.32 लाख हो गयी। यह वृद्धि पिछले 12 महीनों में हुई 9 लाख की वृद्धि से काफी कम थी। बेरोजगार शिक्षित व्यक्तियों की संख्या में अधिकांश वृद्धि बिहार (1.2 लाख), पश्चिम बंगाल (0.7 लाख), तमिलनाडु (0.6 लाख), और महाराष्ट्र (0.5 लाख) में हुई है।

वर्ष 1975–76 की औद्योगिक संभावनाएं

3.41 इस समय बिजली, कोयला तथा इस्पात जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए दृढ़ता से जो प्रयत्न किये जा रहे हैं, उनसे वर्ष 1975-76 में औद्योगिक विकास में वृद्धि की आशा की जा सकती है। लेकिन कृषिजन्य औद्योगिक कच्चे माल की पूर्ति के बारे में स्थिति काफी अनिश्चित है। इस बात के संकेत हैं कि कम से कम वर्ष की पहली छमाही में कृषिजन्य कच्चे माल के कम मिल सकने से कृषि पर आधारित उद्योगों के उत्पादन की वृद्धि करने में खास तौर से रुकावट आतीरहेगी क्योंकि औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में इन उद्योगों का बहुत बड़ा अंश है। मैन्यूफैक्चर की जाने वाली वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि की संभावना भी बहुत कुछ अनिश्चित है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह सोचना कोरी काल्पना होगी कि औद्योगिक उत्पादन में शीघ्र ही बहुत बड़ी वृद्धि होने वाली है।